









## विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की बौद्धिक व शारीरिक क्षमता के लिए कार्य करें : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे एवं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरुवार को अलवर के हल्दीना स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राज्यपाल बागडे ने इस दौरान नई शिक्षा नीति के आलोक में अपने पाठ्यक्रमों को समायोजित, उपयोगी और अधुन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया। उन्होंने महाराजा भृत्हरि को याद करते हुए उनके लिखे हुए शतक और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने पर जोर दिया। उन्होंने बेटियों से कहा कि निडर और बहादुर बनें। उन्होंने कहा कि अन्याय जहां पर हो वहां सबको मजबूती से उसका विरोध कर सामाजिक मूल्यों को मजबूत करना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास की आवश्यकता जताई।

## बाधिन की गतिविधियों के कारण राणथम्भौर में रास्ता बंद

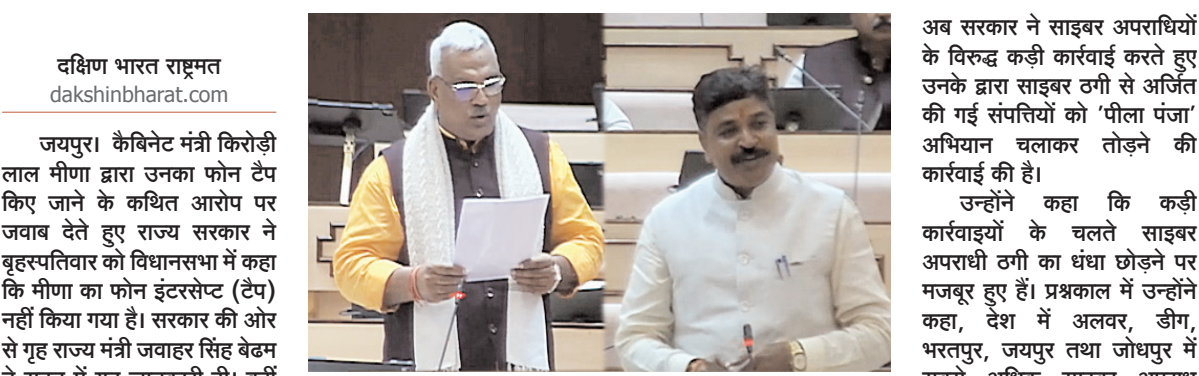
जयपुर। राजस्थान में सर्वांगी माधोपुर जिले के राणथम्भौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास बाधिन टी 84 एरोहेड और उसके दो शावकों द्वारा सांभर का शिकार किये जाने के बाद वन विभाग ने गुरुवार को एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं के लिये गणेश मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाधिन परिवार अभी शिकार के आसपास मौजूद है, ऐसे में विभाग द्वारा राणथम्भौर दुर्ग की ओर जाने वाले पथकों और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के श्रद्धालुओं को गणेश धाम द्वार पर ही रोका जा रहा है। जब तक बाधिन परिवार इस क्षेत्र से दूरी नहीं चला जाता, तब तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। वन विभाग बाधिन और उसके शावकों की लगातार निगरानी कर रहा है। बाधिन एरोहेड और उसके शावकों की राणथम्भौर दुर्ग में अक्सर गतिविधियां बनी रहती हैं। इससे पहले भी करीब चार-पांच बार बाधिन और उसके शावक इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं।

## सरकार कर रही है सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गंभीरता के साथ प्रयास : बाघमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डा मंजू बाघमार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि जयपुर के भांखरोटा दुर्घटना में दोनों वाहन चालकों की लापरवाही से हादसा हुआ है लेकिन अन्य सेफगार्ड होने की दशा में यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील है तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए तथा इन वाहनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मौजूद नियमों की भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद कार्रवाई करते हुए इस सड़क पर मौजूद 33 अनाधिकृत कट में से 32 कटों को बंद कर दिया गया है। एनएचआई की एक अधिकारी को अन्वय स्थानान्तरित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आगामी दस साल की कार्ययोजना भी बनाई गई है, जिसके तहत 2030 तक दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी लाने तथा वर्ष 2033 तक दुर्घटनाओं में 75 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईटीएस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। साथ ही वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है। सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील

# सरकार ने किरोड़ी लाल मीणा का फोन 'टैप' नहीं किया : बेढम



दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

जयपुर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा उनका फोन टैप किए जाने के कथित आरोप पर जवाब देते हुए राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा कि मीणा का फोन इंटरसेप्ट (टैप) नहीं किया गया है। सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सदन में यह जानकारी दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार को अपने मंत्री मीणा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्षी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को व्यवस्था दी थी कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार को बयान दिया जाएगा। बेढम ने कहा, कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से हमारे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान संज्ञान में आया। इसमें उनके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर रखे जाने की बात है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की बात की। जबकि स्वयं मीणा द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। उन्होंने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्चर्य करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा किरोड़ी लाल मीणा का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है।



## संपर्क पोर्टल 2.0 को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा : पंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवारों के जल्द से जल्द निरस्तारण की समीक्षा के लिए राज्य के सभी सम्भागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर की दीर्घी के माध्यम से गुरुवार को बैठक की। बैठक में उन्होंने जिलों के अधिकारियों से संपर्क पोर्टल की वर्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल 2.0 को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। संपर्क पोर्टल पर जयपुर और जोधपुर के परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि ये जिले काफी बड़े भी हैं इसीलिए इसमें परिवारों के अधिक होने की संभावना रहती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परिवारों को निरस्तारित कर इनकी संख्या में कमी लाने के प्रयास करें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवारों के समाधान से आमजन में संतुष्टि का स्तर बढ़ना चाहिए। समाधान होने पर परिवारों को फीडबैक लें कि



## अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता के माध्यम से किया जाए लाभान्वित : दक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गोमन कुमार दक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के दौरान राज्य में सहकारी आन्दोलन को अधिक मजबूत बनाने और अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास सहकारिता में कायम रहे। सहकारिता मंत्री गुरुवार को नेहरू सहकार भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष से संबंधित प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना एवं कैम्पेण्डर के विमोचन के बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से माध्यम से शामिल हुए। दक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, लेकिन देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में वर्ष 2021 से ही कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत 54 पहलों के माध्यम से देश में सहकारी सेक्टर सशक्त हो रहा है। जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र का योगदान 40 प्रतिशत हो, इसके लिए सभी को अपनी भूमिका समझते हुए कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना होगा। दक ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता सेक्टर को प्राथमिकता दे रही है। राज्य बजट में सहकारिता से संबंधित कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं, जिनसे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में व्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का दायरा बढ़ाते हुए 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने की घोषणा की गई है। साथ ही, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी दायरा बढ़ाकर 2.50 लाख गोपाल परिवारों को

## राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से किया बहिर्गमन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान की सोलहवीं विधानसभा के तृतीय एवं बजट सत्र में गुरुवार को कृषि मंत्री डा किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैप मामले में राज्य सरकार के जवाब के बाद विपक्ष के सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया। राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस मामले में सदन में जवाब देते हुए कहा कि डा मीणा सहित किसी का भी कोई फोन टैप नहीं किया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वे सरकार के जवाब से संतुष्ट हैं लेकिन बात यह है कि एक कैबिनेट मंत्री ने फोन टैप की बात की और सरकार कह रही है कि फोन टैप नहीं हुआ तो ऐसे में क्या सरकार उन पर कोई कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष ने डा मीणा को नोटिस भी दिया और नोटिस के जवाब में डा मीणा ने उनका फोन टैप होने के बारे में नकारा नहीं है और कहा है कि उन्हें ऐसी बातें सार्वजनिक स्थल पर नहीं कहनी चाहिए। इस दौरान एक मंत्री ने सदन में तख्ती लहरा दी, इस पर











वित्त मंत्रालय  
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

# गति कृषि विकास में



## समृद्ध अन्नदाता, समृद्ध भारत

किसानों को मिली नई सुविधाएं  
बनेंगी विकसित भारत का आधार



पीएम धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों में उत्पादकता बढ़ाकर 1.7 करोड़ किसानों का विकास



लगभग 7.7 करोड़ मछुआरों, किसानों तथा डेयरी किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की



भारत के समुद्री क्षेत्र के उद्यमियों और किसानों की मदद के लिए, फ्रोजन फिश पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% और फिश हाइड्रोलाइसेट पर 15% से घटकर 5%



कॉम्प्रहेंसिव रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेसिलिएंस कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और निवेश द्वारा स्थानीय कृषि और रोजगार बढ़ाएंगे ताकि प्रवास एक विकल्प बने, मजबूरी नहीं (शुरुआत 100 कृषि जिलों से)



स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण इलाकों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं के लिए 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' का ढांचा तैयार



दालों, खासकर अरहर, उड़द और मसूर में आत्मनिर्भरता के लिए एक खास मिशन

